भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
19.03.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 3170 का उत्तर

दतिया रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास

3170. श्रीमती संध्या राय:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश भर में विकसित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ख) अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है तथा उक्त योजना के अंतर्गत दतिया रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास पर कितनी लागत आई है; और
(ग) उक्त योजना के अंतर्गत भिंड और दतिया जिलों में अंडर-ब्रिज/ओवर ब्रिज के निर्माण की स्थिति क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): मध्य प्रदेश राज्य में स्थित दतिया रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित करने के लिए चिह्नित किया गया है। दतिया स्टेशन पर विकास कार्यों के लिए निविदाएं प्रदान की गई हैं और स्टेशन भवन, प्रतीक्षालय, शौचालय, परिपथन क्षेत्र, जल निकासी व्यवस्था आदि के सुधार कार्य पूर्ण हो चुके हैं और नए पैदल पार पुल के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है।

रेल परियोजनाओं का सर्वेक्षण/स्वीकृति/निष्पादन राज्य-वार नहीं बल्कि क्षेत्रीय रेल-वार किया जाता है, क्योंकि रेल परियोजनाएं राज्यों की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं। रेल परियोजनाओं को लाभप्रदता, यातायात अनुमान, अंतिम स्थान संपर्कता, मिसिंग लिंक और वैकल्पिक मार्गों, संकुलित/संतृप्त लाइनों का संवर्धन, राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों,

संसद सदस्यों, अन्य जन-प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई मांगों, रेलवे की अपनी परिचालनिक संबंधी आवश्यकताओं, सामाजिक-आर्थिक महत्वों आदि के आधार पर स्वीकृत किया जाता है जो चालू परियोजनाओं के थ्रो-फॉरवर्ड और निधियों की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता है।

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेल पर लगभग 7.44 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली 44,488 किमी. कुल लंबाई की 488 रेल अवसंरचना परियोजनाएं (187 नई लाइन, 40 आमान परिवर्तन और 261 दोहरीकरण) योजना/अनुमोदन/निर्माण के चरणों में हैं, जिनमें से 12,045 किमी. लंबाई कमीशन हो चुकी है और मार्च, 2024 तक लगभग 2.92 लाख करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है। सारांश निम्नानुसार है:-

कोटि	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई नई लाइन/ आमान परिवर्तन/ दोहरीकरण (कि.मी. में)	मार्च, 24 तक कमीशन की गई लंबाई (कि.मी. में)	मार्च, 2024 तक किया गया व्यय (करोड़ रुपए में)
नई लाइन	187	20199	2855	160022
आमान परिवर्तन	40	4719	2972	18706
दोहरीकरण/ मल्टीट्रैकिंग	261	19570	6218	113742
कुल	488	44,488	12,045	2,92,470

लागत, व्यय और परिव्यय सहित समस्त रेल परियोजनाओं का जोन-वार/वर्ष-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।

भारतीय रेल पर नए रेलपथों की कमीशनिंग/बिछाने का ब्यौरा निम्नानुसार है:

अवधि	कुल रेलपथ कमीशनिंग	नए रेलपथ की औसत कमीशनिंग
2009-14	7,599 कि.मी.	4.2 कि.मी. प्रति दिन
2014-24	31,180 कि.मी.	8.54 कि.मी. प्रतिदिन (2 गुना से अधिक)

अब तक, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए 1337 स्टेशन चिह्नित किए गए है, जिनमें से 80 स्टेशन मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। मध्य प्रदेश राज्य में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए चिह्नित गए स्टेशनों के नाम इस प्रकार हैं:

राज्य	अमृत स्टेशनों की संख्या	अमृत स्टेशनों के नाम
मध्य प्रदेश	80	अकोदिया, आमला, अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, बानापुरा, बरगवां, ब्योहारी, बेरछा, बेतूल, भिंड, भोपाल, बिजुरी, बीना, बियावरा राजगढ़, छिंदवाड़ा, डबरा, दामोह, दतिया, देवास, गाडरवारा, गंजबासौदा, घोड़ाडोंगरी, गुना, ग्वालियर, हरदा, हरपालपुर, होशंगाबाद, इंदौर, इटारसी जंक्शन, जबलपुर, जुन्नारदेव, करेली, कटनी जंक्शन, कटनी मुरवारा, कटनी साउथ, खाचरोड, खजुराहो, खंडवा, खिरकिया, लक्ष्मीबाई नगर, मैहर, मक्सी, मंडलाफोर्ट, मंदसौर, एमसीएस छतरपुर, मेघनगर, मुरैना, मुलताई, नागदा, नैनपुर, नरसिंहपुर, नीमच, नेपांगर, ओरछा, पांढुर्ना, पिपरिया, रतलाम, रीवा, रूठियाई, सांची, संत हिरदाराम नगर, सतना, सागेर, सीहोर, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, शामगढ़, श्योपुर कलां, शिवपुरी, श्रीधाम, शुजालपुर, सिहोरा रोड, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन, उमरिया, विदिशा, विक्रमगढ़ आलोट

अमृत भारत स्टेशन योजना सहित स्टेशनों के विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण को सामान्यतः योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाओं' के तहत वित्त पोषित किया जाता है। योजना शीर्ष-53 के तहत आवंटन और व्यय का विवरण क्षेत्रीय रेलवे-वार रखा जाता है। मध्य प्रदेश राज्य को सात क्षेत्रों अर्थात् मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा कवर किया गया है। इन क्षेत्रों के लिए, योजना शीर्ष-53 के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 6,002 करोड़ रुपए (संशोधित अनुमान) का आवंटन किया गया है और 2024-25 (फरवरी, 2025 तक) के दौरान 4,961 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है।

रेलवे स्टेशनों का विकास / उन्नयन जटिल प्रकृति का होता है जिसमें यात्रियों और रेलगाड़ियों की संरक्षा शामिल होती है और इसके लिए दमकल विभाग, धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन स्वीकृति इत्यादि जैसी विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। इनकी प्रगति जनोपयोगी सेवाओं को स्थानांतरित करना, अतिलंघन (जिनमें जल/सीवेज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइन, पावर/सिगनल केबल इत्यादि शामिल हैं), यात्री संचलन को बाधित किए बिना रेलगाड़ियों का परिचालन, उच्च वोल्टेज की बिजली लाइनों के निकट

सान्निध्य में किए जाने वाले कार्यों के कारण गति प्रतिबंध आदि जैसी ब्राउन फील्ड संबंधी चुनौतियों के कारण भी प्रभावित होती है और ये कारक कार्य के समापन समय को प्रभावित करते हैं। अत:, इस समय कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

01.02.2025 की स्थिति के अनुसार, मध्य प्रदेश राज्य में 6,336 करोड़ रुपए की लागत पर 306 अदद ऊपरी/निचले सड़क पुलों को स्वीकृत किया गया है, जिसमें दतिया जिले में 57.48 करोड़ रुपए की लागत पर 04 अदद ऊपरी/निचले सड़क पुलों के कार्य और भिंड जिले में 177.53 करोड़ रुपए की लागत पर 04 अदद ऊपरी सड़क पुलों के कार्य शामिल हैं, जो योजना और निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।

****